Part XVII: Languages

Part XVII of the Constitution of India deals with the Languages. It contains provisions regarding the official language of the Union and the rights of citizens to use their own language.

Article 343 provides for the official language of the Union and lays down the provisions regarding the use of Hindi and English for official purposes.

Article 344 provides for the appointment of a Commission to recommend the steps to be taken to progressively use Hindi as the official language.

Article 345 provides for the power of the State Legislature to adopt any one or more of the languages in use in the State as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

Article 346 provides for the special status of the English language for a period of 15 years from the commencement of the Constitution, after which the Parliament may by law determine the status of the English language.

Article 347 provides for the recognition of the regional languages and lays down the provisions regarding the use of such regional languages for official purposes.

Article 348 provides for the power of the President to issue directions for the purpose of securing the proper use of Hindi and English for official purposes, and lays down the provisions regarding the manner in which such directions are to be issued.

Overall, Part XVII of the Constitution of India lays down the provisions regarding the official language of the Union and the rights of citizens to use their own language, and aims to ensure the protection and promotion of linguistic diversity in the country.

भाग XVII: भाषाएँ

भारत के संविधान का भाग XVII भाषाओं से संबंधित है। इसमें संघ की राजभाषा और नागरिकों के अपनी भाषा के प्रयोग के अधिकार के संबंध में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है और राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 344 हिंदी को राजभाषा के रूप में उत्तरोत्तर प्रयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 345 राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपनाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 346 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा की विशेष स्थिति प्रदान करता है, जिसके बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा की स्थिति निर्धारित कर सकती है।

अनुच्छेद 347 क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता प्रदान करता है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 348 सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करता है, और ऐसे निर्देश जारी करने के तरीके के बारे में प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XVII संघ की आधिकारिक भाषा और नागरिकों के अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकारों के बारे में प्रावधान करता है, और इसका उद्देश्य देश में भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करना है।